भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4593 का उत्तर

वर्धा-अकोला-भुसावल खंड की स्थिति

4593. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्धा-अकोला-भुसावल खंड पर तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) डीपीआर परीक्षण के परिणामों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या परियोजना को सभी आवश्यक पर्यावरणीय और सांविधिक मंज़ूरियाँ प्राप्त हो गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा वर्तमान में ये अनुमोदन के किस चरण में है;

(घ) क्या परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा डीपीआर के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) परियोजना के पूरा होने पर विदर्भ और खानदेश क्षेत्रों में यात्रा समय और संपर्क पर संभावित प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए भुसावल-अकोला-वर्धा तीसरी और चौथी लाइन (314 किमी) के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) को मंजूरी दे दी गई है। भौतिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है और डीपीआर तैयार कर ली गई है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए जाने के पश्चात, परियोजना को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय के मूल्यांकन आदि जैसे आवश्यक अनुमोदनों की आवश्यकता होती है। चूँकि, परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करना सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः सटीक समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

इस परियोजना से इस क्षेत्र में लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, अतिरिक्त यात्री और माल यातायात उपलब्ध होगा, माल और सेवाओं का तीव्र परिवहन संभव होगा, परिचालन संबंधी बाधाएं कम होंगी, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होगा, क्षेत्र के लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन उद्योग का विकास होगा और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

भारतीय रेल ने अपनी परियोजना नियोजन प्रक्रिया में गति शक्ति के सिद्धांतों को तुरंत आत्मसात कर लिया है, जिससे परियोजनाओं के मूल्यांकन, स्वीकृति और निष्पादन में तेज़ी आई है। जमीनी सर्वेक्षण, मार्ग संरेखण, वन और वन्यजीवन क्षेत्रों से गुजरने से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय करना, पत्तनों, खदानों, कोयला खदानों से संपर्क स्थापित करना, बीआईएसएजी-एन द्वारा विकसित प्रधानमंत्री गति शक्ति संस्थागत तंत्र के माध्यम से किए जाते हैं। इससे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की गुणवत्ता बेहतर हुई है और परियोजना की लागत में कमी आई है।

अब एकीकृत योजना निर्माण, बेहतर संभार तंत्र दक्षता, प्रथम और अंतिम मील संपर्कता, समग्र संवर्धन और लोगों, माल/पण्यों जैसे कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि की निर्बाध आवाजाही के लिए बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से सभी नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का सर्वेक्षण, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टीमोडाल संपर्कता हेतु अवसंरचना के विकास हेतु बीआईएसएजी-एन द्वारा विकसित प्रधानमंत्री गति शक्ति संस्थागत तंत्र के अंतर्गत किया जाता है।

रेल परियोजना/ओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना/ओं स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना/ओं के पूर्ण होने के समय एवं लागत को प्रभावित करते हैं।

*****